TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(03 February 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कनाडा, चीन और मैक्सिको पर टैरिफ की कार्यवाही और उसकी प्रतिक्रिया
- परमाणु ऊर्जा मिशन एवं छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) में R&D पर बल
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस और भारत में चार नए रामसर स्थलों का जोड़ा जाना
- MCQ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कनाडा, चीन और मैक्सिको पर टैरिफ की कार्यवाही और उसकी प्रतिक्रिया:

परिचय:

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कनाडा, मैक्सिको और चीन से आयात पर टैरिफ लगाए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 फरवरी से शुरू होने वाले, मैक्सिको और कनाडा के सामानों पर टैरिफ लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए।
- हालांकि कार्यकारी आदेश में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि यदि इन देशों ने जवाबी कार्रवाई की, तो इसे पहले से लगाए गए शुल्कों में "वृद्धि या विस्तार" के साथ पूरा किया जा सकता है।

राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ योजना क्या है?

- इसमें चीन से आयातित सभी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत तथा मेक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत कर लगाया गया है।

- इसका एक अपवाद कनाडा के ऊर्जा उत्पाद हैं, जिनमें तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली शामिल हैं, जिन पर 10 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिका हर साल कनाडा, मेक्सिको और चीन के साथ लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार करता है।

राष्ट्रपति ट्रंप ये शुल्क क्यों लगा रहे हैं?

- राष्ट्रपति ट्रम्प ने आयात कर लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) का हवाला दिया, और लक्षित देशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध आव्रजन या मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया।
- आधिकारिक बयान में कहा गया है कि "इसका उद्देश्य अवैध आव्रजन को रोकने और हमारे देश में जहरीली फेंटेनाइल और अन्य दवाओं के प्रवाह को रोकने के उनके वादों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराना है"।
- उल्लेखनीय है कि यह कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार-बार व्यापक शुल्क लगाने की धमकी को पूरा करती है, एक नीति जिसका वे बचाव करते हैं और मानते हैं कि इससे राजस्व उत्पन्न करने, अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने और लाभ उठाने में मदद मिलती है।

कनाडा ने इस टैरिफ पर क्या प्रतिक्रिया दी है?

- कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अनिच्छा से घोषणा की कि कनाडा भी इसी तरह का जवाब देगा, जिसमें 155 अरब अमेरिकी डॉलर तक के आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।
- जस्टिन ट्रूडो ने सवाल किया कि राष्ट्रपति ट्रम्प ऐतिहासिक अमेरिकी-कनाडा साझेदारी को क्यों खतरे में डाल रहे हैं, जिसे उन्होंने "दुनिया ने अब तक सबसे मजबूत साझेदारी" बताया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि "व्हाइट हाउस द्वारा की गई कार्रवाई ने हमें एक साथ लाने के बजाय अलग कर दिया है"।
- कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने के लिए सबसे आगे चल रहे मार्क कार्नी ने भी राष्ट्रपति ट्रम्प टैरिफ की आलोचना की और कहा कि कनाडा "एकजुट" होगा और "एक बुली के खिलाफ खड़ा होगा"।

मेक्सिको ने इस टैरिफ पर क्या प्रतिक्रिया दी है?

- मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने मेक्सिको से आने वाले सभी सामानों पर टैरिफ के जवाब में जवाबी टैरिफ लगाने का आदेश दिया। राष्ट्रपति शिनबाम ने कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के साथ टकराव के बजाय बातचीत चाहती है, लेकिन मेक्सिको को उसी तरह जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- उल्लेखनीय है कि अमेरिका अब तक मेक्सिको का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी बाजार है, और 2023 में मेक्सिको को अमेरिका का निर्यात $322 बिलियन से अधिक था, जबकि अमेरिका ने $475 बिलियन से अधिक मूल्य के मैक्सिकन उत्पादों का आयात किया।
- मेक्सिको के वित्त मंत्री के अनुसार अमेरिकी टैरिफ अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते का "घोर उल्लंघन" है।

इस टैरिफ पर चीन की प्रतिक्रिया क्या है?

- चीन की सरकार ने टैरिफ और राष्ट्रपति ट्रंप की मांग की निंदा की है, जबकि उसने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया है।
- चीन विश्व व्यापार संगठन (WTO) में राष्ट्रपति ट्रंप के इस टैरिफ को चुनौती देगा और प्रभावी होने वाले शुल्क के जवाब में अनिर्दिष्ट "प्रतिवाद" करेगा।
- उल्लेखनीय है कि चीन की यह नरम प्रतिक्रिया कनाडा और मेक्सिको की प्रत्यक्ष प्रतिशोध और गर्म भाषा के विपरीत है, जिससे उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के बीच एक व्यापक व्यापार युद्ध से बचने के लिए कुछ गुंजाइश हो सकती है।
- क्योंकि चीन निर्मित वस्तुओं पर लगाया गया 10%-टैरिफ भी चीन के लिए राहत की बात हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान चीन से आयात पर 60% या उससे अधिक शुल्क लगाने की बार-बार धमकी दी थी।

- हालांकि चीन का सबसे तीखा विरोध फ़ेंटेनाइल को लेकर है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि "फेंटेनाइल अमेरिका की समस्या है और चीनी पक्ष ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापक मादक पदार्थ विरोधी सहयोग किया है"।
- उल्लेखनीय है कि सिंथेटिक ओपियोइड फ़ेंटेनाइल एक नशीली दवा है जो हर साल अमेरिका में हजारों लोगों की ओवरडोज से मौत का कारण बनती है। दवा बनाने के लिए ज़रूरी रसायन ज्यादातर चीन और मैक्सिको में उत्पादित होते हैं।

यूरोपीय संघ की इस कार्यवाही को लेकर प्रतिक्रिया:

- यूरोपीय संघ ने 2 फरवरी को कहा कि उसे कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले पर "खेद" है और अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर टैरिफ लगाया तो वह "दृढ़ता से जवाब देगा"।
- यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने कहा कि यूरोपीय संघ को वर्तमान में अपने उत्पादों पर लगाए जा रहे किसी भी अतिरिक्त टैरिफ के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि प्रवक्ता ने कहा कि "अमेरिका के साथ हमारा व्यापार और निवेश संबंध दुनिया में सबसे बड़ा है। ऐसे में बहुत कुछ दांव पर लगा है"। "सभी क्षेत्रों में टैरिफ उपायों से व्यापार लागत बढ़ती है, श्रमिकों और उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। टैरिफ अनावश्यक आर्थिक व्यवधान पैदा करते हैं और मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं। वे सभी पक्षों के लिए हानिकारक हैं"।

परमाणु ऊर्जा मिशन एवं छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) में R&D पर बल:

चर्चा में क्यों है?

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में छोटे मॉड्युलर रिएक्टरों (SMR) में अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए 20,000 करोड़ रुपये के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की जो 2033 तक में कम से कम पांच ऐसे रिएक्टरों को चालू करने का लक्ष्य रखा है और 2047 तक 100 GW स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता के (नए) लक्ष्य को दोहराया है।
- SMR में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम करने के लिए, सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति अधिनियम के लिए नागरिक दायित्व में संशोधन करने का भी इरादा रखती है।
- ऐसे में नया मिशन और बजट भाषण में परमाणु ऊर्जा का उल्लेख, भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा को दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित करता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य:

- वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2047 तक कम से कम 100 GW परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अभी, भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 7,480 MW है, जिसमें 23 परमाणु रिएक्टर शामिल हैं। सरकार की योजना 2031-32 तक इस क्षमता को तिगुना करके 22,800 MW करने की है, जब 2017 में स्वीकृत और वर्तमान में निर्माणाधीन दस नए स्वदेशी रूप से विकसित रिएक्टर चालू हो जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि सौर या पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विपरीत, परमाणु ऊर्जा मांग पर बिजली उत्पादन का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है, और मौसम संबंधी रुकावटों के प्रति संवेदनशील नहीं है।

परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र को जोड़ने की योजना:

- उल्लेखनीय है कि, 100 GW लक्ष्य तक पहुँचने का मतलब है 2032 और 2047 के बीच 15 वर्षों में पाँच गुना विस्तार करना है। यह हर साल लगभग 5-6 GW परमाणु ऊर्जा का जोड़ने के समान है, और यह निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता।

- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन अब तक भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (भाविनी) के पास रहा है। पिछले कुछ वर्षों में नीतिगत बदलाव ने NTPC या NHPC जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को परमाणु संयंत्रों के स्वामित्व और संचालन के लिए NPCIL के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने की अनुमति दी गयी है।
- वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन करेगी ताकि परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र के प्रवेश को सुगम बनाया जा सके। परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (CLND) अधिनियम 2010 के प्रावधानों में भी संशोधन किया जाएगा, जो परमाणु दुर्घटना से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए संयंत्र संचालकों को जिम्मेदार ठहराता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पूरी तरह रोका न जाए।

स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के लिए मिशन:

- बजट भाषण में सरकार की 2033 तक पांच छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) को "संचालित" करने की इच्छा का उल्लेख है। पिछले साल के अपने बजट भाषण में,

वित्त मंत्री ने भारत के स्वदेशी SMR अर्थात भारत लघु रिएक्टर (BSR) बताया था। वित्त मंत्री में बजट भाषण में SMR में अनुसन्धान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रूपये की बात की है।

- BSR भारत के दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR) होने की संभावना है, जिन्हें सुविधाओं (जैसे 'निष्क्रिय सुरक्षा') के साथ संशोधित किया गया है। भारत के पास PHWR में विशेषज्ञता है, जिनमें से 20 चालू रिएक्टर हैं, जिनमें से 15 'छोटे' (220 MW) हैं। इसके अलावा, SMR को नए ईंधन को संभालने के लिए बनाया जा सकता है जिसमें थोरियम हो सकता है।
- भारत में थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। ऐसा ही एक नया ईंधन है 'ANEEL (एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच लाइफ)', जो उच्च स्तर (14 से 19 प्रतिशत के बीच) तक संवर्धित यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण है। इस तरह, यह बिना क्रमिक 3-चरणीय योजना का इंतजार किए, देश को थोरियम उपयोग का विकल्प देता है, जो सात दशकों के बाद भी पहले और दूसरे चरण के बीच अटकी हुई लगती है।

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) क्या होते है?

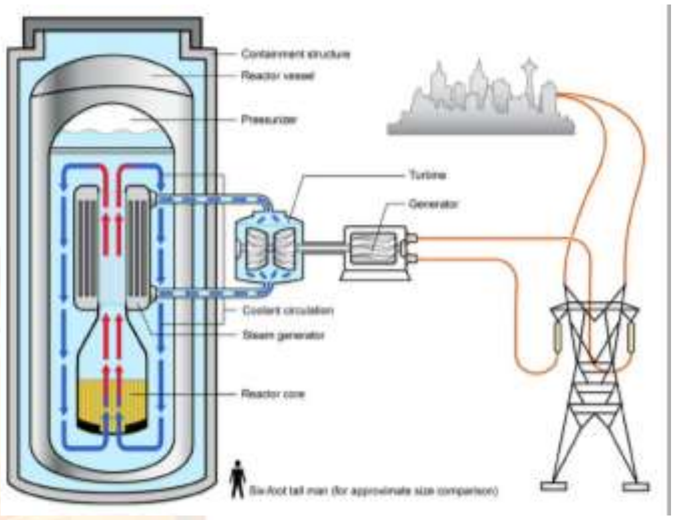

- छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी प्रति इकाई बिजली उत्पादन क्षमता 30 से 300 MW तक होती है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग एक तिहाई है।
- गतिशील और लचीली तकनीक होने के कारण, इसके सिस्टम और घटकों को फ़ैक्टरी-असेंबल करना और इंस्टॉलेशन के लिए एक इकाई के रूप में एक स्थान पर ले जाना संभव बनाता है।
- SMR को 90% से अधिक क्षमता कारकों के साथ 40-60 वर्षों तक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन्हें ऑफ-साइट निर्मित किया जा सकता है जिससे निर्माण समय की काफी बचत होती है। इनमें आपातकालीन नियोजन क्षेत्र और निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली के कम आकार जैसे संभावित तैनाती लाभ भी हैं।

वैश्विक स्तर पर SMR को बढ़ावा:

- वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान इस दशक के भीतर SMR तकनीक को साकार करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
- अब तक, वैश्विक स्तर पर दो SMR परियोजनाएँ परिचालन चरण में पहुँच चुकी हैं। एक रूस में एकेडमिक लोमोनोसोव फ्लोटिंग पावर यूनिट नामक SMR है जिसमें 35 मेगावाट के दो मॉड्यूल हैं और मई 2020 में इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हो गया था। दूसरी चीन में HTR-PM नामक एक प्रदर्शन SMR परियोजना है जिसे दिसंबर 2021 में ग्रिड से जोड़ा गया था।
- भारत भी, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के तरीके के रूप में, और प्रौद्योगिकी-आधारित विदेश नीति पिच के रूप में SMR को बंडल करने, दोनों ही के रूप में SMR क्षेत्र में नेतृत्व की स्थिति के लिए जोर दे रहा है।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस और भारत में चार नए रामसर स्थलों का जोड़ा जाना:

परिचय:

- 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि धरती पर सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। इस वर्ष, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम "हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना" थी।
- उल्लेखनीय है कि इसके पहले, 1 फरवरी 2025 को भारत ने आर्द्रभूमि पर वैश्विक समझौते रामसर कन्वेंशन के तहत चार नए रामसर स्थलों की घोषणा की - झारखंड में उधवा झील, तमिलनाडु में तीर्थंगल और सक्करकोट्टई और सिक्किम में खेचोपलरी।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस:

- 1971 में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
- भारत 1982 से कन्वेंशन का एक पक्ष है।

आर्द्रभूमियाँ क्या होती हैं?

- आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र हैं जो बारहमासी या मौसमी रूप से पानी से ढके रहते हैं, जैसे दलदल और झीलें। रामसर कन्वेंशन में आर्द्रभूमि को "दलदली, दलदली भूमि, पीटलैंड या पानी के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी हो या अस्थायी, जिसमें पानी स्थिर हो या बहता हो, ताजा, खारा या नमकीन हो, जिसमें समुद्री पानी के क्षेत्र शामिल हैं जिनकी गहराई कम ज्वार पर छह मीटर से अधिक नहीं होती है"।

आर्द्रभूमियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती है?

- उल्लेखनीय है कि आर्द्रभूमियाँ जैव विविधता के महत्वपूर्ण भंडार हैं, जल संरक्षण में सहायता करते हैं और कई प्रवासी पक्षियों, जलीय प्रजातियों और पौधों के जीवन के लिए आवास प्रदान करते हैं।

- आर्द्रभूमियाँ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन (पृथक्करण) के माध्यम से भी जलवायु स्थितियों को विनियमित करने में मदद करते हैं, अर्थात, वायुमंडल से कार्बन को ग्रहण करने और भंडारण करने में।
- उल्लेखनीय है कि आर्द्रभूमि अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित करके और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करके बाढ़ और तूफान से पर्यावरण की रक्षा करती है।
- आर्द्रभूमि दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से हैं, जिनकी तुलना वर्षावनों और प्रवाल भित्तियों से की जा सकती है।

आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन:

- आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर 1971 में ईरान के एक छोटे शहर रामसर में हुए थे। तब से आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को 'रामसर कन्वेंशन' के रूप में जाना जाता है।
- रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में आर्द्रभूमि के नुकसान को रोकना और जो शेष हैं उनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग और प्रबंधन के माध्यम से संरक्षण करना है।

- किसी आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित करने के साथ देश आर्द्रभूमि के संरक्षण और इसके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रबंधन ढांचे की स्थापना और देखरेख करने पर सहमत होते हैं।
- **रामसर आर्द्रभूमि के मानदंड:**
  - ➢ रामसर कन्वेंशन के तहत, किसी आर्द्रभूमि को रामसर वेटलैंड साइट के रूप में घोषित किया जाता है *अगर वह वेटलैंड कन्वेंशन के तहत* ***निर्धारित नौ मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती*** **है।**
  - ➢ **पहला मानदंड प्रतिनिधि, दुर्लभ या अद्वितीय आर्द्रभूमि प्रकार वाली साइटों** को संदर्भित करता है, और **अन्य आठ जैविक विविधता के संरक्षण के लिए** अंतरराष्ट्रीय महत्व की साइटों को कवर करते हैं।

आर्द्रभूमि के लिए क्या खतरे हैं?

- उल्लेखनीय है कि, आर्द्रभूमि को बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है। रामसर कन्वेंशन के ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक (2018) के अनुसार, 1970 और 2015 के बीच वैश्विक आर्द्रभूमि का 35% हिस्सा नष्ट हो गया है। आर्द्रभूमि को प्रभावित करने वाले मुख्य खतरे निम्नलिखित हैं:

- **असतत विकास:** पिछले 300 वर्षों में दुनिया की 87% आर्द्रभूमि आवास, उद्योग और कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए खो गई है।
- **प्रदूषण:** वैश्विक अपशिष्ट जल का लगभग 80% बिना उपचार के आर्द्रभूमि में छोड़ दिया जाता है।
- **आक्रामक प्रजातियां:** आर्द्रभूमि में वन्यजीव विशेष रूप से आक्रामक प्रजातियों के लिए असुरक्षित हैं, जिन्हें अक्सर मनुष्य द्वारा लाया जाता है, क्योंकि पानी उन्हें फैलने और बढ़ने के लिए आसान मार्ग प्रदान करता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** वर्षा पैटर्न और तापमान में परिवर्तन आर्द्रभूमि और उनमें रहने वाले वनस्पतियों और जीवों के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करते हैं।

भारत में चार नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया:

- केंद्र सरकार ने भारत में चार नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है, जिससे कुल संख्या बढ़कर 89 हो गई है।
- नए नामित रामसर स्थलों में तमिलनाडु में सक्करकोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेर्थंगल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम में खेचोपलरी वेटलैंड और झारखंड में उधवा झील शामिल हैं।

- उल्लेखनीय है कि सिक्किम और झारखंड के लिए यह घोषणा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि उन्होंने अपना पहला रामसर स्थल हासिल कर लिया है। साथ ही कुल 20 रामसर स्थलों के साथ, तमिलनाडु अब सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला भारतीय राज्य बन गया है।
- इस घोषणा से आर्द्रभूमि संरक्षण के मामले में भारत की स्थिति मजबूत हुई है, क्योंकि यह एशिया में सबसे अधिक और दुनिया में तीसरा सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है।

MCQs

1. चर्चा में रहे 'अमेरिका की कनाडा, चीन और मैक्सिको पर टैरिफ की कार्यवाही' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अमेरिका की इस टैरिफ योजना के तहत चीन, मेक्सिको और कनाडा से आयातित सभी वस्तुओं पर 25 प्रतिशत कर लगाया गया है।
2. टैरिफ योजना का उद्देश्य इन देशों होने वाले आयात को नियंत्रित करके अमेरिका द्वारा अपने व्यापार घाटे को कम करना है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(d)

2. आर्द्रभूमि पर 'रामसर कन्वेंशन' के तहत किसी आर्द्रभूमि को इस सूची में शामिल करने के लिए इस कन्वेंशन के तहत तहत निर्धारित नौ मानदंडों में से न्यूनतम कितने मानदंडों को पूरा करना होता है?

(a) किसी भी एक मानदंड को।

(b) कम से कम पांच मानदंड को।

(c) कम से कम 7 मानदंड को।

(d) सभी नौ मानदंड को।

Ans:(a)

3. चर्चा में रहे 'खेचोपलरी वेटलैंड' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह सिक्किम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली रामसर साइट है।
2. पूर्वी हिमालय में 1700 मीटर की ऊंचाई पर, सिक्किम में स्थित इस झील को 'इच्छा पूर्ति करने वाली झील' के रूप में धार्मिक मान्यता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)

4. बजट 2025-26 में घोषित 'परमाणु ऊर्जा मिशन' में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान एवं विकास के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है?

(a) 10,000 करोड़ रुपया

(b) 20,000 करोड़ रुपया

(c) 50,000 करोड़ रुपया

(d) 70,000 करोड़ रुपया

Ans:(b)

5. वैश्विक स्तर पर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के विकास की वस्तुस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अब तक, वैश्विक स्तर पर दो केवल SMR परियोजनाएँ परिचालन चरण में पहुंचीं हैं।
2. एक चीन की जिसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है दूसरी अमेरिका की जिसकी अभी ट्रायल स्तर परिचालन हो रहा है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(a)